खण्ड ६ संख्या २५

बिहार विधायिका सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि - २५ मार्च १९४९

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नोत्तर	१-३
विधायिका परिषद् से प्राप्त संदेश	४
आय-व्ययक: अनुदानों के अभियाचन पर मतदान। ...	४-३४
शिक्षा [स्वीकृत]	५
२६ मार्च के कार्य सूची में परिवर्तन।	३४
आय-व्ययक: अनुदानों के अभियाचन पर मतदान। ...	३४-३७
[अपरान्ह की दूसरी बैठक — ६-१५ बजे।] ...	३७
विधायन कार्य : राजकीय विधेयक : ...	३७
बिहार फाइनेन्स बिल, १९४९, [१९४९ का वि: स० १०] (क्रमशः)	३७
बिहार फाइनेन्स बिल सभा के अधिकार के बाहर है या नहीं तथा बिहार एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट १९४२ के बिना संशोधित हुए, बिहार फाईनेन्स बिल सभा में आ सकता है या नहीं, इन सब नियमापत्तियों पर माननीय प्रमुख का निर्णय। ...	५०-५७
बिहार फाइनेन्स बिल १९४९, [१९४९ का वि० स० १०] [स्वीकृत हुआ]	५७

की ओर से और मजदूरों की ओर से स्टैन्डिंग आर्डर प्रमाणित करने का अनुरोध हुआ है ;

(ग) क्या यह वात सही है कि लेवर कमिश्नर ने दो महीने पहले इस सम्वन्ध में एक सम्मेलन बुलाया था ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ ?

मानीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह :

(क) उत्तर 'हां' में है।

(ख) उत्तर 'हां' में है।

(ग) उत्तर 'हां' में है सुनवाई को स्थगित कर देना पड़ा क्यों दोनों पक्ष वाले पहले ही से ऊख पेरने में लगे थे और यह भी समझा गया कि जब तक औध्योगिक न्यायाधिकरण (इंडस्ट्रियल ट्रिव्यूनल) का निर्णय, जो उस समय विचाराधीन (सर्टिफिकेशन) था, हो न जाय तब तक प्रमाणी करणको रोक दिया जाय।

हरिजन छात्रावास के लिये जमीन की व्यवस्था।

५१६। सरदार हरिहर सिंह : क्या वेल फेयर विभाग के माननीय मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(क) भिन्न भिन्न जगहो व्योरेवार किन किन स्कूलो तथा कालेजों के लिए हरिजन छात्रावास बनाने के लिए जमीन की व्यवस्था सरकार ने की है और कितने रुपये अलग अलग इसके लिए खर्च किए गए है ;

(ख) अभी तक कितने ऐसे छात्रावास बनसके और क्या रकम अलग अलग खर्च हुए हैं ?

माननीय श्री जगलाल चौधरी :

(क) हरिजन छात्रावास बनाने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, औरंगावाद गया, छपरा, गोपालगंज, मुंगेर, भागलपुर में जमीन प्राप्त करने की उचित कारवाई की है परन्तु अभो तक जितनी सूचनाऐ मिल सकी है उनसे यही जान पड़ता है कि औरंगावाद (गया) और पटने में जमीन प्राप्त हो गयी है और इसके लिए क्रमशः ५६४ रु० ८ आ० और २४,६१८ रु० ८ आ० खर्च हुए है। गोपालगंज में हरिजन छात्रावास के लिए जमीन की ए० वी० स्कूल की प्रबन्ध कारिणी कमिटी ने सरकार को रजिष्ट्री कर दी है।

(ख) अभी तक कुछ कठिनाइयों के कारण उपरोक्त जगहों में छात्रावास नहीं वन सके परन्तु निकट भविष्य में काम शुरू हो जाने की सम्भावना है।